

14.05 hrs

Regarding Hardships Faced by Fishermen Community

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर ? 12.

श्री के. सी. वेणुगोपाल जी ।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you very much, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I call the attention of the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

?Hardships faced by fishermen community.?

2 पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निम्नलिखित बातों को सभा पटल पर रखता हूँ :-

मात्स्यिकी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह क्षेत्र लगभग 30 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है, जो सीमांत समुदायों से हैं । इस क्षेत्र को ?सनराईज़ सैक्टर? के रूप में जाना जाता है और इसमें रणनीतिक हस्तक्षेपों (इंटरवेनशन्स), उत्पादन में वृद्धि, निर्यात, प्रौद्योगिकी को अपनाने और रोजगार सृजन के माध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है ।

मात्स्यिकी क्षेत्र की विशाल क्षमता को पहचानते हुए भारत सरकार ने जून, 2019 में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी का एक अलग मंत्रालय बनाया । इसके अतिरिक्त, 2015 से, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 38,572 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है ।

विभिन्न योजनाओं और नीतिगत पहलों के कारण मत्स्य उत्पादन और समुद्री खाद्य निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया है और इसी अवधि के दौरान सी फूड एक्सपोर्ट 30,213 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 60,523.89 करोड़ रुपए हो गया है ।

फिशिंग हारबर (एफएच) और फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी) फिशिंग वेसल्स के लिए सुरक्षित लैंडिंग, बर्थिंग, लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं । पिछले 10 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने 9,735.89 करोड़ रुपए की कुल लागत से 67 फिशिंग हारबर (एफएच) और 50 फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी) के

निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें केरल में 668.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से 13 फिशिंग हारबर्स और उनकी ड्रेजिंग की परियोजनाएं शामिल हैं। इससे लगभग 48,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुनिश्चित होगी, जिससे 9 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाने वाली गतिविधियों में मछुआरों की आजीविका को मजबूत बनाने और उनके कल्याण के लिए सहायता शामिल है, जैसे ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (जीएआईएस), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण सहायता, वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों जैसे सी वीड कल्टीवेशन सहित समुद्री कृषि (मैरीकल्चर), ओपेन सी केज कल्चर, बिवाल्व कल्टीवेशन, ओरनामेन्टल फिशरीस, पारंपरिक मछुआरों के लिए नावें और जाल, वेस्सल कम्यूनिकेशन तथा सपोर्ट सिस्टम, डीप सी फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स का उन्नयन आदि। सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत मछुआरों और तटीय समुदायों को प्रदान की गई सहायता द्वारा तटीय मछुआरा समुदायों पर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव कम होते हैं।

भारत के समुद्र तट में लगभग 3,477 तटीय मत्स्यन गाँव शामिल हैं, जिनमें मछुआरे आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में मात्स्यिकी पर निर्भर हैं। तटीय मछुआरों के कई गाँव तटीय कटाव (कोस्टल इरोशन), बाढ़ और चक्रवात जैसे जलवायु प्रभावों से ग्रस्त हैं, जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन और आजीविका को प्रभावित करते हैं। इन परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत भी एक पहल की है, जिसमें सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए तट रेखा के करीब स्थित 100 कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (सीएफवी) को क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ मछुआरा गाँव बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ यह पहल की गई है।

केरल में विभिन्न प्रकार के समुद्री और अंतर्देशीय जलीय संसाधन मौजूद हैं और यहां मात्स्यिकी विकास की काफी अच्छी क्षमता है। पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल राज्य के लिए 1358.10 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 12 फिशिंग हारबर्स का विकास और आधुनिकीकरण, वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान 1,79,316 मछुआरों को आजीविका सहायता, पारंपरिक मछुआरों को नावें और जाल (200 यूनिट्स), मछुआरों, मत्स्य किसानों और हितधारकों (7,930 संख्या) के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (179 संख्या), आर्टिफिशियल रीप्स (42 यूनिट्स), मत्स्य सेवा केंद्र (10 यूनिट्स), सागर मित्र (222 संख्या) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, केरल में 9 इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस और 6 क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस भी स्वीकृत किए गए हैं।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने ऑफशोर एरियास मिनरल एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2002 पारित किया है, जो वर्ष 2010 में प्रभावी हुआ। ऑफशोर एरियास मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पारिस्थितिकी संतुलन (इकोलोजिकल बैलेन्स), जैव-विविधता तथा मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय द्वारा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और इंपोर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज (आईसीएमबीए) के रूप में अधिसूचित पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर ऑफशोर ब्लॉक बनाए गए हैं ।

ऑफशोर एरिआज मिनरल (ऑक्शन) नियम 2024 के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन अधिकार (ओपेरेशन्स राईट) के पहले, बोलीदाताओं को प्रोडक्शन ऑपरेशन्स शुरू करने संबंधी लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है ।

इसके अलावा, ऑफशोर एरिआज मिनरल कोन्सरवेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2024 के प्रावधानों के अनुसार, प्रोडक्शन प्लान के अनुसार ही कोई भी प्रोडक्शन को ऑपरेट किया जा सकता है । मछुआरों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं पर प्रोडक्शन प्लान और पर्यावरण प्रबंधन योजना एनवायोरमेंट मैनेजमेंट प्लान (EMP) की तैयारी के दौरान विशेष रूप से विचार किया जाएगा, जिसे नियमों के तहत प्रत्येक पट्टेदार को एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन प्लान शुरू करने से पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

केरल तट के ऑफशोर सेंड ब्लॉक बेसलाइन से 12 नौटिकल माईल्स से अधिक दूर है और फिशिंग ग्राउंड्स की सुरक्षा और मछुआरों की आजीविका के पहलुओं से संबंधित मुद्दों को प्रोडक्शन प्लान तैयार करते समय और पर्यावरण प्रबंधन योजना में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान को केरल के तट पर अपतटीय खनन गतिविधियों (ऑफ शोर माईनिंग एक्टिविटीस) के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए नामित किया गया है ।

उपर्युक्त के आलोक में, यह देखा जा सकता है कि माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पहले से ही कार्रवाई की जा रही है ।

SHRI K. C. VENUGOPAL: I rise here today, not just as the representative of the people but as a voice of the community that lives and dies by the sea. A community whose lives are deeply connected with the waves of the ocean. Their cries are often unheard by the roaring waves of indifference and neglect. I speak for our fishermen, the unsung heroes who go to unpredictable seas to bring food to our table but they live in the shadow of neglect.

Across the vast coast of Gujarat to Kanyakumari and Bengal to deep south and in the Andaman Island and Lakshadweep, they live everyday at the mercy of nature, stormy seas, harsh winds and uncertain times. They are the people who feed our nation but struggle to feed their own families.

Sir, in this country, there is only one job which does not have the guarantee of getting wages. Everyday fishermen go to sea for fishing ? morning, evening, night, everytime, they go for fishing. Sometimes, they come with fishes and sometimes, they come with empty hands.

*I am sad to say that this is the only job in India, and the whole world, for which the worker is not assured of wages after performing his duty. This is the job of a

fisherman. We have discussed on many occasions in this House about the plight of fishermen community. Sir, none of the discussions in the past has helped to solve their problem. That is why, by this Calling Attention, I brought up this issue in this House.*

Sir, they do not seek riches or luxuries. All they ask for is dignity of life without fear, a life where their children can dream beyond the horizon. When I talk about the fishermen, my colleagues from Kerala will remember 2018 when the flood ravaged the God's own country, it was the fishermen who came with their boats. They reached every corner and they rescued thousands of people. They were the army; they were the angels but do we remember them now?

Once we described the fishermen as the "Army of Kerala". During the time of flood in Kerala, people were suffering and many of them were on the verge of death. These poor fishermen rescued the people using their own boats. They are the "Army of Kerala".

At that point of time, everybody called them the army of Kerala. But, are we remembering them now? This is a question. I need an answer to this question. India is one of the largest fish producing countries. Today, Morning also, hon. Minister replied to a Question. The sector provides food, nutrition, and livelihood to millions yet what do we give back to those people.

Sir, GDP numbers are very good. Our fishermen contributed in this booming industry ? 1.24 per cent of Indian Gross Value Added and 7.28 per cent to agriculture GVA in 2018-19, with an average growth rate of 7.53 per cent in fish production. India's marine fisheries potential is immense. In the morning, you spoke about it.

Our Exclusive Economic Zone spans over 2.02 million square kilometres yet the wealth from this remains concentrated in a few hands while the true custodians of the sea, the fishermen, remain in chains of poverty. It breaks my heart to witness this painful irony.

Every time, I travel across the vast coastal stretches of my constituency, Alappuzha, I see men and women whose lips taste of salt, not the salt of the ocean, but the salt of tears, tears of hardship, tears of neglect. These are the tears of those who have given everything to the sea and received nothing but despair in return.

Sir, like coastal fishermen, inland fishermen are also present. Apart from the sea-going fishermen, we have a considerable number of inland fishermen. The inland fisheries activities are conducted across an extensive network of rivers and canals, 1.95 lakh kilometre floodplain lakes, 8.12 lakh hectare backwaters, ponds and tanks, reservoirs with an estimated fish production potential of about 17 million tonnes.

Currently, inland fisheries have emerged as a major contributor to the overall fish production in this country. Despite India being the second largest fish producer globally, the Government policies and priorities are misguided. The marine fishery sector is a unique and irreplaceable source of livelihood for millions, including our inland fishing communities. Yet, we lack even basic reliable data on the socio-economic conditions of our fishermen. How can we uplift the community when we cannot even measure their suffering?

We have institutions like the National Fisheries Development Board (NFBD) and the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) producing extensive research on fish, spices, and marine resources. But where is the data on those who bring those resources to our shores? Where is the comprehensive national register of fishermen and their living standards? Are they not worthy of recognition, of being counted, of being seen?

Our coastal zones of India are among the most productive ecosystems in the world. Yet, there are existential threats from sea-level rise, coastal erosion, and flooding. The Government must answer a fundamental question: Who controls our coasts? Who is monopolising our marine wealth while the traditional custodians are pushed aside?

Hon. Speaker, it is alarming that one company operates a port or terminal in every 500 kilometres along India's 7,516-kilometre-long coastline. Only one company has the monopoly. The group now controls 14 ports and terminals, representing 27 per cent of India's total port volume. Ports from Haldia in West Bengal to Vizhinjam in Kerala are under their control. What is the problem? In these areas, the total privatisation of these ports is now creating problems for the poor fishermen. Thousands of poor fishermen are being displaced; their livelihoods are snatched away and their futures are stolen.

Sir, I have already told you about inland fishermen. We have many rivers and backwaters. I think you have been there in my constituency. One of the most

beautiful backwaters in the world is Vembanad Lake. It is called the gateway of backwaters.

माननीय अध्यक्ष : मुझे आप लेकर ही कब गए? मैंने तो देखा ही नहीं ।

SHRI K. C. VENUGOPAL : Sir, I am inviting you. Our Parliamentary Affairs Minister likes that. Vembanad Lake is one of the most beautiful lakes. But now-a-days, the poor fishermen are not in a position to fish there due to complete weed infestation and the area is also shrinking day by day.

Therefore, our water bodies have to be purified. Only then can proper fishing be done in that area. We need to clean our rivers and backwaters, remove the weeds, and bring life back to these waters. Our fishermen deserve a chance to live with dignity.

Now, I am coming to a major point, which I have brought to your notice earlier. The Government of India is going for offshore mining. The government speaks of the blue economy. Under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2023, private companies will soon drill our sea beds, extracting crude oil, gas, and minerals.

What will be left for the fishermen; whose livelihoods are tied to these waters? I asked a question. Hon. Member, Hibi Eden asked a question in this Session only. The reply given by the mining minister is: ?Before notifying the above blocks in offshore areas, the Central Government had consulted several key ministries, including Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Department of Fisheries under Ministry of Fisheries.? This is a direct question to hon. Minister. Has the Fisheries Department done a study on the impact of this offshore mining? I have a data of the researches being done by our scientists. They belong to the Geological Survey of India, the National Institute of Ocean Technology, the National Institute of Oceanography, the National Centre for Polar and Ocean Research, the National Geophysical Research Institute; the Earth System, and other science organisations are the agencies involved. These people have not studied any impact on offshore mining. There are people who have done this study. I will tell you about those people. Their studies suggest that offshore sand mining is often poorly managed, leading to severe environmental, social and economic consequences. There is a knowledge gap in offshore sand mining management and sustainability and we need to conduct additional research to fill this gap.

According to FAO GLOBEFISH Research Programme, Vol. 122, 2016, the main expected impacts from seabed mining are: - changes in the seabed landscape by removing nodules from the seafloor, changes in the marine habitat that sustain different forms of life, sediment plumps, which will cause a reduction of oxygen and light in the water column and the introduction of metal into the water column, disruption of the seafloor and redistribution of sediments, causing some benthic ecosystems and creatures to be buried, very slow ecosystem recovery from the changes to the seafloor, and displacement of marine life.

Sir, our scientists are predicting such a serious impact on offshore mining. Our Department of Fisheries has already consented for this. For whom is this Fisheries Department working? Is this Department working for the mining people or the fishermen? My direct question to the Minister is this. Is he working for the mining companies or the poor fishermen of this country?

Sir, how can you allow this mining without a proper study? So, without a proper study they are doing mining. Hon. Member Mr. Premachandran has already raised this issue. In areas of Kollam and Alappuzha, which is my constituency, they have already done tenders. Now, they are going to do mining. Entire fishermen community is agitated. The Kerala Legislative Assembly has unanimously passed a Resolution. They have written to the hon. Minister in this regard, but, there is no action. The Government has to come forward. Yesterday, hon. LoP, Shri Rahul Gandhiji, has written to the Prime Minister to withdraw this mining activity. Somebody has to stop this mining. The Government has to come forward to stop the mining work and rescue the poor fishermen of this country.

We cannot allow these things to happen. You are not allowing even construction of houses for poor fishermen. When the fisherman is going to construct a house, you are saying that CRZ norms are there. They are not allowed to construct a small house. But, now, large-scale mining is going on in the sea, and there is no problem. There is no environmental impact study. Nothing is there. Now, the Government is saying: ?If somebody took a tender, the tender company has to do environmental impact study.? What is it? It is like letting the fox guard the hen house. This is what is happening here. The company has to do environmental impact study.

Basically, this is ridiculous. This reckless pursuit of profit is robbing our fishermen of their heritage, their dignity, and their means of survival. Our coastal communities, environmentalists, and marine scientists are united in protest, as are

the majority of the political parties. Then why is the Government of India doing all these things?

My submission to the Minister of Fisheries is this. You are a senior leader of the ruling party. Please tell the Prime Minister to at least stop this mining process. I have already talked about the housing issue and CRZ norms. Some amendments have been made, but they are not sufficient. The poor fishermen do not have the means to construct their dwelling houses. The Government must come forward with a clear-cut, flexible idea on CRZ. The major point of sea erosion has already been raised.

Sir, this is shocking. Seventy per cent of the world's beaches are vanishing in India. The ocean waves and currents are eating away our shores. In undeveloped areas, erosion comes and goes, but in developed areas, it is a disaster. A study by the National Centre for Coastal Research shows that Kerala is one of the worst-hit States. More than 46 per cent of Kerala's coast eroded due to sea erosion. The coasts are not just land; they are our borders and are as important as our northern and western boundaries. The sea brings dangers such as terrorism, trafficking, and drug smuggling. However, erosion is a threat too. It is taking away land and destroying the lives of fishermen and coastal communities. These are the same people who risk their lives in floods to save others. Now we turn away as the sea destroys their homes.

Sir, I would like to make one more point about subsidised kerosene. Kerala alone has 1.95 lakh fishermen who go out to sea every day. The sea is their life. It gives a living to 8.04 lakh fisherfolk. Those traditional fishermen use small boats with outboard motors that run on kerosene. There are around 30,000 such boats in Kerala, but the kerosene they need is just not there. Kerala fishermen require 51,000 kilolitres of kerosene every year. However, the Central Government keeps cutting the quota. In 2021, Kerala received only 11,640 kilolitres. In 2023, it was only 7,160 kilolitres. For 2023-24, it is just 3,300 kilolitres. This year, it is shocking at only 648 kilolitres. This is nothing other than cruelty. Therefore, subsidized kerosene must be increased. Since they are not getting sufficient kerosene, they have to depend on loans. Now, the entire fishing community is in a debt trap and is in a suicidal mood.

*A situation in which it is difficult to live, kerosene oil is not available for them. If they go to the sea, they do not get fishes. As a last resort if they take loan from banks and these banks torture these fishermen to get repayment. Only the fisher

community faces such an atrocity. No one is here to help them. Offshore mining will affect the entire environment. No one is ready to listen to the fisher community. We have raised this Calling Attention to remind the Government that they must listen to the problem of the fishing community.*

I would request the hon. Minister to look into this issue. You have given a statement that covers some issues. But what are you doing specifically for fishermen's housing, their drinking water, and their debt? Nothing has been covered. Please think about the poor fishermen of this country.

Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. आर. बालू जी, आपको केवल प्रश्न पूछना है। आप सीनियर लीडर हैं।

? (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I understand, Sir. I will be very short. Kindly give me a few minutes.

With a heavy heart, I would like to call the attention of the hon. Minister for Fisheries to the sad plight of Indian fishermen, especially those from Tamil Nadu, who are subjected to hardship at the hands of Sri Lankan security forces day in and day out. Every day, the Government of Tamil Nadu is writing to the Central Government to intervene and ensure that proper action is taken, or the Government of Sri Lanka should be advised properly so that things may not go wrong.

Sir, sometime back I made an observation, and on 18th February the hon. Minister for External Affairs, Dr. S. Jaishankar wrote to me. This is also a subject matter that is connected with two Ministries. He wrote and I quote:

??Prime Minister during the State visit of President Anura Kumara Disanayaka on 15-17 December, 2024 urged President Disanayaka to treat the fishermen issue as a humanitarian one with livelihood concerns, as well as to avoid use of force under all circumstances. Further, I raised the issue of frequent arrests, longer sentences and penalties levied on Indian fishermen with the Sri Lankan President as well. In addition, we have requested President Disanayaka for the early release and repatriation of detained Indian fishermen and boats, and convening of next round of fishermen-level talks?.

The ground reality is different. Yesterday, I had a discussion with the President of the Fishermen Association of Rameswaram. He categorically said that the Minister is saying something, but on the ground things are different. Each and every day, the security forces are coming and are arresting them. They are not only arresting the fishermen, but also taking their boats. They are taking away everything to their destination. Finally, the fishermen are arrested.

For your information, 20 fishermen are in jail for the past six months. What sin have they done? It is for more than six months that they are languishing in jail, and more than 70 fishermen -- in and out of Rameswaram, Pudukkottai and elsewhere -- are in various jails for inquiry. They are being kept there for inquiry.

Sir, I would not take much time. Actually, the fishermen of that area who are going to earn their daily bread are being harassed. A small country that is having friendly connections with India is just making a lot of nuisance for our fishermen. This is not fair. My only request is this. It seems that the hon. Prime Minister is likely to go to Sri Lanka shortly. I do not know the exact date, etc., but during discussions with President Dissanayake there should be a discussion about it and finally they should have a lasting peace agreement with all the stake holders, especially with the fishermen of Sri Lanka and Tamil Nadu, India. Further, representatives of both the Governments should take immediate action. Otherwise, things will go wrong. Thank you, Sir.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, hon. Speaker, Sir. This may be the first Calling Attention during this Budget Session. We are thankful to the hon. Speaker for allowing such an important issue, and I would also thank hon. learned friend, Shri K. C. Venugopal for calling the attention of the hon. Minister regarding the fisheries issue.

I am not going to repeat the issues which have already been enlisted by my learned friend, Shri K. C. Venugopal. There are no words to explain the pathetic condition of the fishermen in the coastal areas. It is just like that of the tribal people in the mountain areas.

Fishing is the only main source of income of the fishermen, but due to unsustainable fishing practices and depleting fishing stocks, it is impacting the livelihoods of the fishermen and health of the marine ecosystem. Rising sea temperatures, changing ocean currents and increased storm activity can disrupt the fishing grounds and threaten fish population, and pollution from industrial and

agricultural sources can contaminate fish population and make them unsafe for consumption. The quantity of abundant fish wealth has declined like anything throughout the country after the tsunami and Ockhi disasters hit the State of Kerala.

In such a situation, the UPA regime had passed a very revolutionary law ? the Right to Forest Act ? giving tribal people the right to enjoy benefits of the forest. I would like to seek a clarification from the hon. Minister on whether the Government of India is thinking of bringing the Right to Sea Act in order to protect the interests of the fishermen in the country.

माननीय अध्यक्ष : आप तो रूल्स के जानकार हैं । इसमें केवल स्पष्टीकरण ही मांग सकते हैं ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, he has rightly explained everything regarding Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act which was passed in the year 2023. There is deep sand mining in the offshore. Parappur and Alappuzha in my constituency have 85 kms of length. Now, the tender has been invited to start the sand mining.

There is no doubt that the marine ecosystem will be disrupted severely and it will be adversely affecting the coastal fishermen at large. There is an agitation going on in the State of Kerala. Even yesterday, the Leader of the Opposition rightly pointed that that it will be adversely affecting the interests of the coastal fishermen.

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात खत्म कर लीजिए ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, would the Government reconsider and recall the tender? It should not be done without conducting the environmental impact assessment.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी ।

मेरा सदस्यों से आग्रह है कि इसमें केवल एक-एक प्रश्न पूछ लें । इसमें आप लम्बा भाषण न करें ।

DR. SHASHI THAROOR : Sir, I have five clarifications to seek from the hon. Minister because these are the issues that I have been raising for 15 years in this House without a satisfactory response. I will be very brief on each of them.

माननीय अध्यक्ष : आप 15 साल से मुद्दा उठा रहे हैं । क्या आपका मुद्दा दूसरों ने ले लिया है?

DR. SHASHI THAROOR: Sir, the first issue is regarding coastal erosion which affects my constituency gravely. Ferocious monsoons have been devastating our coastline,

destroying homes and livelihoods, and the fisher folk are suffering terribly because of lack of adequate seawalls and groins. This issue was raised this morning by my colleague, Hibi Eden ji. The hon. Minister's reply put the entire onus on the State Government. The State Government says they do not have the resources. भारत माता की धरती जा रही है। यह समुद्र से जो आक्रमण हो रहा है, हमारी धरती जा रही है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में 64 स्कवेयर किलोमीटर चली गई है। उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? I would like to request the hon. Minister to assume the responsibility for protecting Indian territory.

The second issue is regarding lack of fishing harbours. You have talked about the PMMSY supporting 100 coastal villages, but the coastal villages are not enough. They need harbours. In my constituency, we have 28 per cent of Kerala's fishermen, and they have absolutely no harbours other than one major port that is now coming up. Hundreds of fishermen are literally unable to make a living. They have long-standing demands for fishing harbours in places like Poonthura and Valiyathura but no action has been taken. We would appreciate some clarification from the hon. Minister.

Sir, the third issue is regarding kerosene shortage. This issue has been raised by many hon. Members.

माननीय अध्यक्ष : जो विषय एक बार उठ गये हैं, उनको दोबारा क्यों उठा रहे हैं?

डॉ. शशि थरूर : सर, मेरे पाँच प्रश्न हैं। Once again, the Government says it would like to encourage our fishing people to shift to cleaner fuels like LPG, PNG and so on, but they do not have engines. These are poor people. They have kerosene-fuelled engines on their traditional fishing craft. If they cannot give subsidised kerosene, can they subsidise new engines to use the fuel the Government wants them to use? That clarification should be given.

माननीय अध्यक्ष : यह मुद्दा उठा दिया है।

? (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, please give me one second. I had asked a question last month to which I got a reply from the hon. Minister. The reply from the hon. Minister says very clearly that they have not conducted an environmental impact assessment on offshore mining. When can that be done?

And finally, I have also raised in this House the issue of persistent illegal fishing practices such as bull trawling and bear trawling in the waters of Kerala. We have

asked the Government in this House to actually engage the Coast Guard and the Navy to protect our fisherfolk and their livelihood. Again, will the Government, in the clarification, let us know what they are doing about this? These issues have been raised in the House earlier.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Hon. Speaker Sir, thank you for this great opportunity. I would like to congratulate the senior Member Shri K.C. Venugopal for this Calling Attention which I wholeheartedly support because this is a very important matter. Sir, I have a specific question to the hon. Minister. We have state-of-the-art institutions in India like the Central Marine Fisheries Research Institute, CIFT, CIFNET, KUFOS, CSIR and many other organizations related to scientific study of the ocean and the marine-related activities. Does any of these organizations have done a scientific study on offshore mining and its environmental impact? How can the Government of India give the tender of the environmental impact study to the same company which does the offshore mining? It is disastrous. I would like you to intervene in this matter.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Hon. Speaker Sir, I fully associate with the opinion expressed by hon. Shri K.C. Venugopal and other Members. I have one question also. The coastal wealth faces frequent climate disruption like cyclone and extreme weather. Does the Government of India have any large-scale climate resilience? Has the Central Government conducted any studies in mitigating its impact? Considering the success of the geotube offshore breakwater project in some places in Kerala shores, will the Central Government investigate and expand this innovative mode to other coastal regions with provision of adequate fund?

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में तुरहा ताल है। मैदानी क्षेत्रों में जितने ताल और नदियाँ हैं, वहाँ की दूसरी समस्याएँ हैं। मछुआरों के नाम पर नाव भी नहीं होती है। बड़े-बड़े ठेकेदार एक मछुआरे को पकड़ते हैं और पोखरों से मछली मारने के लिए नावों के ठेके ले लेते हैं। मछुआरों के नाम से नाव और जाल नहीं होते हैं। वे केवल मजदूरी पर रख लिये जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कम से कम मछुआरों को नाव, जाल और ठेके इस तरह से दिये जाएं ताकि वे स्वावलंबी हो सकें।

यह नियम है कि मछुआरे नदियों, तालाबों और पोखरों के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं और वहीं पर मंडई बनाकर रहते हैं। मत्स्यपालन विभाग के द्वारा यह व्यवस्था भी है कि उन मछुआरों के घर बनाये जाएंगे। लेकिन अभी तक उन मछुआरों के लिए कोई घर भी नहीं बना है, मैं यह सरकार से कहना चाहता हूँ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Hon. Speaker Sir, I would like to get a clarification from the hon. Minister. Over 200 boats have been

taken away by the Sri Lankan Navy and it is being nationalized by the Sri Lankan Government. Will the Fisheries Department or the Government of India give some compensation to these fishermen who have lost their boats? Earlier, it was done, Sir. I want to know whether they will give compensation because the Tamil Nadu Government is giving it.

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुम्बई बंदर में कोंकण का 720 किलोमीटर का किनारा है। वहाँ के मछुआरे यहाँ पर अपना काम करते हैं। उनको दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या यह है कि उनको किरोसीन नहीं मिलता है। उनको केरोसीन और डीजल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उनको डीजल भी सब्सिडी पर मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलती है। उसके बाद फिशरमेन और तकलीफ में आते हैं।

दूसरी बात यह है कि हवा में जब बदलाव होता है, लाल झण्डा जब समय पर फहराया जाता है, तब वे शिपिंग के लिए जाते हैं। इसलिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। ये दो काम महत्वपूर्ण हैं।

मुम्बई पोर्ट अथॉरिटी जो कुछ डेवलपमेंट करती है, अगर वह मछुआरों को विश्वास में लेकर करे, तो इससे उनको सहायता होगी।

धन्यवाद।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने कई बातों की चर्चा की है। उसमें से एक बात यह है कि जो लगभग 30 मिलियन मछुआरे भाई हैं, वे गरीब हैं, वास्तव में वे गरीब हैं, उनके प्रति सरकार का इनडिफरेंस और नेगलेक्ट है। यह बात सही नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार ने ही उनकी गरीबी पर ध्यान दिया और उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाईं। आज उसका परिणाम है कि हमारा मत्स्य उत्पादन पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

आपने भी इस देश में वर्षों तक शासन किया, आपने वर्ष 2013 तक शासन किया। वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी आए। आपके समय में तो मछुआरे भाई भुखमरी की कगार पर थे।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज हम यह बताएंगे, माननीय सदस्य को भी यह बताएंगे कि प्रधान मंत्री जी ने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए, जिसके कारण आज मछुआरे समुदाय के लोग सुखमय जीवन जी रहे हैं और कुछ हद तक उनकी कठिनाई दूर हुई है।? (व्यवधान)

वेणुगोपाल जी, जब हम आपको आईना दिखा रहे हैं, तो अपना चेहरा देखकर आपको क्यों चिढ़ हो रही है? आप अपना तो चेहरा देखिए कि आपने क्या किया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी ये ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे थे, पहले हम उसी का जवाब दे देते हैं। इस देश में पहले ऑफशोर माइनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सबसे पहले ऑफशोर माइनिंग का अगर किसी ने कॉन्सेप्ट लाया तो उसे यूपीए सरकार ने लाया और इस सदन में ऑफशोर एरियाज़ मिनरल (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 पास कराया और इसके बाद यह हुआ है।? (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल : वर्ष 2002 में कौन था?? (व्यवधान) वर्ष 2002 में यूपीए नहीं था, वर्ष 2002 में वाजपेयी जी थे ।? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय सदस्य, आप पूरी बात तो सुनिए, आपको हम पूरी बात बता रहे हैं ।? (व्यवधान) आप पूरी बात कहां सुन रहे हैं?? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वर्ष 2010 में इन्होंने रूल्स बनाए । आज तक कोई ऑफशोर माइनिंग केरल में या किसी समुद्री तट पर प्रारम्भ ही नहीं हुआ है । फिर उसके प्रभाव या कुप्रभाव का सवाल ही कहां है? यह कहीं नहीं हुआ है ।

महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि नवम्बर, 2024 में 13 ब्लॉक्स के लिए एन.आई.टी. जारी हुए हैं और उसमें मात्र 3 ब्लॉक्स हैं, जो केरल के हैं और वे भी 12 नॉटिकल माइल्स से बाहर के हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में आता है । फिर आप कहां से ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे हैं? आज तक तो ऑफशोर माइनिंग प्रारम्भ ही नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, सारे लोग यह कह रहे हैं । यह पूरा मामला खनन मंत्रालय से संबंधित है । हमने खनन मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त की है, उसके आधार पर हम इनको बता रहे हैं ।

महोदय, हम इनको बताना चाहते हैं कि ये जो मछुआरे समाज के प्रति इनडिफरेंस और नेग्लेक्ट की बात कर रहे थे, तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि वर्ष 2014 के बाद जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, तो हर क्षेत्र पर, हर क्षेत्र के लोगों पर उन्होंने ध्यान दिया । उनकी यह सोच रही है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने फिशरीज सेक्टर पर ध्यान दिया । उन्होंने वर्ष 2019 में इस विभाग को अलग किया । उसके पहले उन्होंने ?ब्लू रिवॉल्यूशन? के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों और मछुआरे भाइयों के कल्याण की योजना की शुरुआत की । वर्ष 2019 में उन्होंने फिशरीज डिपार्टमेंट को अलग किया, ताकि उस पर ध्यान केन्द्रित करके उस क्षेत्र में काम किया जा सके । उसके बाद उन्होंने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना चलायी । इन सबके बाद उन्होंने फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफ.आई.डी.एफ.) बनाया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और भी योगदान किया जा सके । यह उनका प्रयास रहा । इसके कारण पूरे देश में आज बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास हुआ ।

अभी शशि थरूर साहब बोल रहे थे । शशि थरूर साहब मुझसे भी मिले थे । उनकी समस्या के साथ मुझको सहानुभूति है । मैंने उनको बताया भी है कि आपकी समस्या के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उसका रास्ता है कि राज्य सरकार से रिश्ता थोड़ा ठीक कर लीजिए, तो आपका बाकी सब कल्याण हो जाएगा । ? (व्यवधान) अब उनके पास पैसे नहीं हैं । थरूर साहब, आपको देने के लिए नहीं हैं । आप थोड़ा रिश्ता सुधार लीजिएगा तो आपका पैसा भी निकल आएगा । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये तो अपोज़िशन में हैं, रिश्ता क्यों सुधारेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण पूरे कोस्टल इलाके में फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स का विस्तार हुआ । वैसल के लिए सुरक्षित बर्थिंग बनाई गई । लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए सारे प्रयास किए गए । उसका परिणाम है कि हमने बताया कि एफआईडीएफ के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट हुआ । वे केरल की बात कर रहे हैं । हम

केरल की भी बात बता देते हैं कि 1359.10 करोड़ रुपये की योजना केरल राज्य के लिए भी स्वीकृत हुई। इसलिए कि मोदी सरकार का यह मानना है कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। सबके लिए समान रूप से विचार करना है। सबका उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। तब विकसित देश का निर्माण होगा। केरल में 12 फिशिंग हार्बर्स का विस्तार हुआ, मॉडर्नाइज़ेशन हुआ। एक लाख 69 हजार 316 मछुआरा भाइयों को प्रतिबंध की अवधि में सहायता प्रदान की गई। वहां के मछुआरा भाइयों को नाव दी गई, गरीब लोगों को जाल दिया गया। कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम चला कर उनमें कौशल विकास और क्षमता निर्माण कराया गया। आर्टिफिशल रिब्स का निर्माण हुआ। मत्स्य सेवा केंद्र का वहां गठन हुआ। 996 मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजिस हैं। वे चर्चा कर रहे थे पीने के पानी की, सारी सुविधाओं की, उन सारी सुविधाओं का वहां प्रावधान किया गया है। क्लाइमेट रेज़िलेंट विलेजिस का निर्माण भी केरल में स्वीकृत किया गया है। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को उसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। मछुआरा भाइयों की सारी समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी की सरकार चिंतित है। उसके अलावा मोदी जी सरकार ने मछुआरा भाइयों के लिए सोशल और इकोनॉमिकल तथा उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम किसने चलाई? ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम मोदी जी की सोच का परिणाम है कि जब मछुआरा भाइयों की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। अगर गंभीर रूप से घायल है तो ढाई लाख रुपये और कम घायल हैं तो 25 हजार रुपये की सहायता उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड किसकी योजना है? प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। किसके उत्थान के लिए है? उन मछुआरा भाइयों के उत्थान के लिए है। वीड कल्टीवेशन किसकी सोच है? इस सरकार की सोच है। मैरिकल्चर, उनकी आर्थिक उन्नत के लिए है। ओपनसी केज कल्चर, ऑनर्नमेंटल फिशरीज़ को बढ़ाया गया, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। परंपरिक मछुआरों के लिए नाव और जाल की व्यवस्था की गई। डीप सी वैसल्स के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया। फिशिंग वैसल्स का अपग्रेडेशन हुआ। ट्रांसपोर्ट, जिसकी चर्चा बालू साहब कर रहे थे और कई साथी कर रहे थे कि हमारे फिशरमैन फिशिंग करते हुए बॉर्डर पार कर जाते हैं।

हमारे फिशरमैन फिशिंग करते हुए बॉर्डर पार कर जाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा हथियार है, जो हमारे मछुआरे भाइयों को मदद करता है। हमारे मछुआरे भाई हमारे देश की सीमा को जैसे ही क्रॉस करेंगे, उनको यह ट्रांसपोर्ट सिग्नल देगा कि आप देश की सीमा क्रॉस कर रहे हैं। यह सेटलाइट से जुड़ा हुआ है। इसे किसी भी एंड्रॉइड फोन से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से उनको सूचना मिलेगी। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनको समुद्री तूफान की सूचना मिलेगी। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनको यह जानकारी भी मिलेगी कि कौन से इलाके में आपका कैच ज्यादा संख्या में उपलब्ध है। वहां आप फिशिंग करने का काम कीजिए। इससे उनका डीजल बचेगा, उनका किरोसीन बचेगा, उनको मेहनत कम करना पड़ेगा और कैच उपलब्ध होगा। वे इस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। वे वेसल्स के मालिक के साथ जुड़े रहेंगे। एक लाख मछुआरा भाइयों को मुफ्त में ट्रांसपोर्ट देने के लिए सरकार का फैसला है। कई राज्यों में इसका काम शुरू हो गया है। यह हमारे मछुआरे भाइयों को दिया जा रहा है। आज उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो गई।

महोदय, एक सौ कोस्टल विलेज को हंड्रेड परसेंट संपोषण के साथ कोस्टल फिशरमैन रेसेलिफ्ट विलेज के रूप में चिन्हित किया गया है। उनका चयन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछुआरे भाइयों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट हेतु फंड निर्धारित किया गया है। उनको जीपीएस की सुविधा दी जाती है। उनको लाइफ जैकेट दिया जाता है। डिस्ट्रेस एलर्ट एवं ट्रांसमीटर की सुविधा उनको दी जाती है। उनको सर्च एंड रेस्क्यू बीकेन दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं किसके लिए हैं? इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था हमारे मछुआरे भाइयों के लिए किया गया है। मछुआरा भाइयों की चिंता मोदी सरकार ने की है। आपकी सरकार ने इतने दिनों तक

उनकी चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के इसी प्रयास का परिणाम आज दिख रहा है। आप फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं। ? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL : I have a point of order. ? (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वेणुगोपाल साहब कह रहे थे कि मछुआरे भाई सुबह जाते हैं, शाम को बिना मछली के आ जाते हैं, उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा, वे भूखे मरेंगे। वर्ष 2013-14 तक जब आपकी सरकार थी, 95.5 लाख टन फिश प्रोडक्शन होता था। मोदी जी की सरकार के दस साल के शासन काल में 184.02 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। यह प्रोडक्शन कौन कर रहा है? यह प्रोडक्शन हमारे वही मछुआरे भाई कर रहे हैं, जो समुद्र से मछली मार कर लाते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करते हैं और अपनी रोजी-रोटी के लिए भी काम करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में आपके शासनकाल में 30,212 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता था। आज वर्ष 2023-24 में 60,523 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा है। इन दस वर्षों में हमने दोगुना एक्सपोर्ट करने का काम किया है।

महोदय, झींगा उत्पादन के बारे में कहना चाहूंगा कि इनके शासनकाल में झींगा उत्पादन 3.22 लाख टन होता था। मोदीजी के शासनकाल में 11.84 लाख टन झींगा का उत्पादन हुआ है। आप कह रहे हैं कि फिशरिज सेक्टर में कोई प्रयास नहीं हुआ है। फिशरमैन पर ध्यान नहीं दिया गया। फिशरमैन नेग्लेक्टेड हैं। फिशरमैन इनडिफरेंट हैं। यह क्या तरीका है? ऐसा नहीं है। आपके जीवीए के बारे में भी बता देता हूँ। हमारे जीवीए में फिशरिज सेक्टर का 9.08 परसेंट का रेगुलर ग्रोथ है। वर्ष 2024-15 में जीवीए में 0.844 परसेंट फिशरिज का कंटीब्यूशन था। आज यह बढ़ कर 1.12 परसेंट हो गया है। यह हमारी उपलब्धि है। आप कह रहे हैं कि जीवीए में कृषि के ओवरऑल स्थिति क्या है? वर्ष 2014-15 में जीवीए में कृषि का ओवरऑल कंटीब्यूशन 5.12 परसेंट था। आज यह बढ़ कर 7.2 परसेंट हो गया है। इसमें 41.79 परसेंट का ग्रोथ है। आपको क्या समझ में आएगा? यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय, बालू साहब और कई सदस्यों ने श्रीलंका के साथ बात करने की बात कही। ? (व्यवधान) श्रीलंका में जो नावें जब्त होती हैं, जब हमारे मछुआरे भाई श्रीलंका के बार्डर में चले जाते हैं, तब की बात है। ? (व्यवधान)

14.55 hrs

At this stage, Shri K. C. Venugopal, Shri T. R. Baalu, Shri N. K. Premachandran and some other hon. Members left the House.

-

हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 6 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं। ? (व्यवधान) ऑनरेबल प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार इस मामले को उठाया है। ? (व्यवधान) विदेश मंत्रालय लगातार इस मामले को उठा रहा है और जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है। ? (व्यवधान) उसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं। ? (व्यवधान) मोदी सरकार में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। ? (व्यवधान) मछुआरे भाइयों का उत्थान हो रहा है। उनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

14.56 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं ।